गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 266
दि. 28.01.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

एसिड अटैक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

नई दिल्ली। देश में लगातार सामने आ रहे एसिड अटैक के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह अपराध दहेज हत्या से कम गंभीर नहीं है और इस पर केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि ठोस और प्रभावी कानूनी दखल की आवश्यकता है। इसी गंभीर टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे एसिड अटैक से जुड़े मामलों की विस्तृत और समग्र जानकारी चार सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करें।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि अदालत केवल कुल मामलों की संख्या से संतुष्ट नहीं होगी। राज्यों को साल-दर-साल दर्ज हुए एसिड अटैक मामलों का पूरा विवरण देना होगा। इसमें यह बताना अनिवार्य होगा कि कितने मामलों में एफआईआर दर्ज की गई, कितनों में चार्जशीट दाखिल हुई, कितने मामलों में ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया और कितने अब भी लंबित हैं। अदालत ने यह भी कहा कि न्याय प्रक्रिया में देरी कहां और क्यों हो रही है, इसे चिन्हित करना बेहद जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों तक ही सीमित न रहते हुए हाईकोर्ट और अन्य अपीलीय अदालतों में चल रहे मामलों का ब्योरा भी मांगा है। कोर्ट यह जानना चाहती है कि एसिड अटैक से जुड़े मामलों में दोषियों या पीड़ितों की ओर से कितनी अपीलें दाखिल की गई हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। अदालत का मानना है कि इस तरह का विस्तृत डेटा सामने आने से न्याय व्यवस्था की कमियों और कमजोर कड़ियों की पहचान की जा सकेगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक पीड़िता का सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइल भी मांगा है। राज्यों को यह जानकारी देनी होगी कि पीड़िता की शैक्षणिक योग्यता क्या है, वह रोजगार में है या नहीं, उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है और एसिड अटैक

के बाद उसके जीवन पर क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि इन जानकारियों के आधार पर ही पीड़िताओं के लिए प्रभावी पुनर्वास नीति तैयार की जा सकती है।

इलाज और पुनर्वास को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने राज्यों से पूछा है कि उनके यहां एसिड अटैक पीड़ितों के लिए कौन-कौन सी पुनर्वास योजनाएं लागू हैं और उनका वास्तविक लाभ पीड़ितों तक पहुंच रहा है या नहीं। इसके साथ ही पीड़ितों के इलाज पर अब तक कितना खर्च हुआ है, भविष्य में कितना खर्च संभावित है और सरकार की ओर से कितनी आर्थिक सहायता दी गई है, इसका पूरा विवरण भी मांगा गया है। कोर्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों को केवल मुआवजा ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिले।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जबरन एसिड पिलाने के मामलों पर विशेष चिंता जताई। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों के आंतरिक अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे उनकी पीड़ा और जटिल हो जाती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस तरह के मामलों का अलग से पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया जाए, ताकि उनकी गंभीरता को समझते हुए विशेष कदम उठाए जा सकें।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी अहम संकेत दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराधों के लिए कानून में बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और दोषियों के लिए असाधारण रूप से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि मौजूदा कानूनी प्रावधान इस अपराध की भयावहता के अनुपात में अपर्याप्त साबित हो सकते हैं।

यह पूरी सुनवाई एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर हो रही है। याचिका में मांग की गई है कि दिव्यांगता की कानूनी परिभाषा का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि जबरन एसिड पिलाने से आंतरिक अंगों को नुकसान झेलने वाले पीड़ितों को भी दिव्यांग माना जा सके। याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसा होने से पीड़ितों को बेहतर मुआवजा, समुचित इलाज और सरकारी सहायता मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस दिशा में बड़े और निर्णायक कदम उठाए जा सकते हैं।

महाकाल के द्वार पर न्यायिक दखल नहीं वीआईपी दर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

नई दिल्ली। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि धार्मिक स्थलों के आंतरिक प्रबंधन और पूजा-पद्धति से जुड़े फैसले न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे में नहीं आते और ऐसे विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार मंदिर प्रबंधन को ही है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें वीआईपी दर्शन को लेकर दायर याचिका को पहले ही खारिज कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी की ओर से यह दलील दी गई थी कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में कुछ खास लोगों को विशेष दर्जे के आधार पर प्रवेश की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद

14 में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया था कि जब भगवान महाकाल के सामने सभी भक्त समान हैं, तो फिर वीआईपी और आम भक्त के बीच भेदभाव क्यों किया जाए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अदालत यह तय नहीं कर सकती कि मंदिर के गर्भगृह में कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं। यह फैसला मंदिर प्रशासन और प्रबंधन समिति का विषय है, न कि न्यायपालिका का। पीठ ने कहा कि धार्मिक संस्थानों की अपनी परंपराएं, व्यवस्थाएं और व्यावहारिक सीमाएं होती हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अदालतें मंदिरों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगेंगी, तो इसके दूरगामी और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर गर्भगृह के भीतर समानता के मौलिक अधिकार को सख्ती से लागू किया गया, तो आगे चलकर लोग अन्य मौलिक अधिकारों, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अन्य संवैधानिक अधिकारों का भी दावा करने लगेंगे, जिससे धार्मिक स्थलों की व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो सकती है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अदालत के रुख को देखते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और कहा कि वह इस मुद्दे को मंदिर प्रबंधन और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने यह तर्क दिया कि वीआईपी जैसी कोई कानूनी श्रेणी नहीं है और किसी भी नागरिक को केवल उसके पद, हैसियत या प्रभाव के आधार पर विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को शिवलिंग के पास जाकर जल अर्पित करने की अनुमति दी जाती है, तो एक सामान्य भक्त को भी वही अधिकार मिलना चाहिए। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी इसी तरह की याचिका को खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वीआईपी की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है और मंदिर के भीतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाए, यह मंदिर प्रबंधन समिति और जिला कलेक्टर के प्रशासनिक विवेक का विषय है। हाईकोर्ट ने यह भी माना था कि सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।

गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब एटीएस की कार्रवाई से टला संभावित हमला

अहमदाबाद। गुजरात में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने समय रहते नाकाम कर दिया है। इस कार्रवाई में एटीएस ने उत्तर प्रदेश के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की कट्टर विचारधारा से प्रभावित होकर राज्य में आतंक और दहशत फैलाने की योजना बना रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की इस सफलता को अहम माना जा रहा है, क्योंकि आरोपी के पास से गैरकानूनी हथियार बरामद हुए हैं और प्रारंभिक जांच में उसके इरादे बेहद खतरनाक पाए गए हैं।

एटीएस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान फैजान शेख के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के डुंडावाला का रहने वाला है। फिलहाल वह गुजरात के नवसारी जिले के चारपुल इलाके में रह रहा था। एटीएस ने रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लंबे

समय से कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों से प्रभावित था और इंटरनेट व अन्य माध्यमों के जरिए अल कायदा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की विचारधारा से जुड़ चुका था।

एटीएस अधिकारियों ने बताया कि फैजान शेख एक विशेष संगठन से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। उसका उद्देश्य राज्य में भय और अस्थिरता का माहौल पैदा करना था। इसी मंशा के तहत उसने अवैध रूप से हथियार और गोला-बारूद हासिल किया था। जांच एजेंसियों ने उसके पास से हथियार बरामद किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका इस्तेमाल पहले किसी आपराधिक गतिविधि में तो नहीं हुआ था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हथियार उसे कहां से और किन माध्यमों से मिले।

हालांकि एटीएस ने सुरक्षा कारणों से इस मामले में अभी अधिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के डिजिटल उपकरणों और संपर्कों की गहन जांच की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या फिर अकेले ही इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। जांच एजेंसियां इस बात को भी खंगाल रही हैं कि क्या उसके संबंध किसी अन्य संदिग्ध या पहले से गिरफ्तार आतंकियों से जुड़े हुए थे।

यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी गुजरात एटीएस ने आतंकी साजिशों का पर्दाफाश किया है। पिछले साल नवंबर में एटीएस ने एक डॉक्टर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जो हथियारों और केमिकल की मदद से बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे। उन आरोपियों में तेलंगाना निवासी डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद भी शामिल था, जो बेहद खतरनाक रासायनिक पदार्थ रिसिन तैयार कर रहा था। रिसिन एक अत्यंत जहरीला पदार्थ होता है, जिसे अरंडी के बीजों को प्रोसेस करने के बाद बचे कचरे से बनाया जाता है और इसकी थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है। उस मामले में उत्तर प्रदेश के दो अन्य लोगों को डॉ. सैयद को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

ताजा गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आतंकी संगठन युवाओं को कट्टर विचारधाराओं के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ऐसे मामलों में सतर्कता बेहद जरूरी है और समय पर मिली सूचना से कई निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती है।

एआई से बदलेगी पुलिसिंग की तस्वीर, सुरक्षा खतरों को पहले ही पहचानने की तैयारी

नई दिल्ली। देश में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी कदम उठाया है। प्रौद्योगिकी आधारित पुलिसिंग को नई ऊंचाई पर ले जाने के उद्देश्य से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने पुलिस बल में समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया है कि देशभर में करीब 70 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को एआई के प्रयोग और उससे जुड़ी तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए, ताकि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को समय रहते भांपा जा सके।

उच्च स्तरीय बैठकों में यह साफ तौर पर कहा गया है कि आधुनिक दौर की पुलिसिंग में एआई अब केवल एक सहायक उपकरण नहीं, बल्कि अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। बदलते अपराध के स्वरूप, साइबर अपराधों में तेजी, संगठित अपराध, आतंकी गतिविधियों और भीड़ आधारित हिंसा जैसे खतरों को देखते हुए सरकार का मानना है कि पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर तकनीक आधारित, डेटा-संचालित और पूर्वानुमानित पुलिसिंग को अपनाना समय की मांग है। इसी सोच के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे एआई को अपनी पुलिस व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाएं।

गृह मंत्रालय इस पूरी कवायद के तहत एक व्यापक और एकीकृत एआई ढांचा तैयार करने जा रहा है। इस ढांचे का उद्देश्य खुफिया जानकारी जुटाने, वास्तविक समय में संभावित खतरों की पहचान करने, अपराध के पैटर्न का विश्लेषण करने और उभरते सुरक्षा जोखिमों का पहले से आकलन करना है। अधिकारियों के अनुसार, एआई आधारित प्रणालियों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों की स्वचालित टैगिंग, बहु-स्रोतों से डेटा का संकलन और उसका त्वरित विश्लेषण संभव हो सकेगा। इससे पुलिस की निर्णय प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि अधिक सटीक और प्रभावी भी बन सकेगी।

इस योजना का एक अहम पहलू राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी नैटग्रिड को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करना है। नैटग्रिड पहले से ही विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से आने वाले डेटा को एक मंच पर लाने का काम करता है। अब जब इसे एआई आधारित विश्लेषण से जोड़ा जाएगा, तो बड़ी मात्रा में उपलब्ध सूचनाओं से पैटर्न निकालना, संदिग्ध नेटवर्क की पहचान करना और संभावित खतरों की भविष्यवाणी करना कहीं अधिक आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि इससे आतंकवाद, संगठित अपराध और गंभीर अपराधों से निपटने की क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

सरकार का जोर केवल तकनीक विकसित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव संसाधन को भी उसी स्तर पर तैयार करने पर है। इसी कारण राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उनके कम से कम 70 प्रतिशत पुलिसकर्मी एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से एआई से जुड़े विशेष पाठ्यक्रम पूरे करें। यह भारतीय कानून प्रवर्तन के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पहलों में से एक मानी जा रही है। प्रशिक्षण के जरिए पुलिसकर्मियों को यह समझाया जाएगा कि एआई टूल्स का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर कैसे किया जाए, डेटा की व्याख्या कैसे हो और तकनीक व मानवीय विवेक के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए।

केंद्र सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से आगे बढ़कर पूर्वानुमानित पुलिसिंग को अपनाना है। इसका अर्थ यह है कि अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, एआई के जरिए पहले ही यह आकलन कर लिया जाए कि कहां, कब और किस तरह का खतरा उत्पन्न हो सकता है, ताकि समय रहते उसे रोका जा सके। अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से न केवल अपराध दर पर अंकुश लगेगा, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास भी मजबूत होगा।

नए लेबर कोड के खिलाफ केरल सरकार का मोर्चा, केंद्र की नीतियों को बताया मजदूर हितों पर हमला

तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के खिलाफ खुलकर विरोध का ऐलान कर दिया है। राज्य के श्रम मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने विधानसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र की मौजूदा श्रम नीतियां मजदूर विरोधी हैं और केरल सरकार इन्हें किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए केंद्र पर हर संभव दबाव बनाएगी और जरूरत पड़ी तो राजनीतिक व संवैधानिक स्तर पर भी संघर्ष करेगी।

यह मुद्दा सदन में उस समय उठा, जब सीपीआई(एम) विधायक पी. नंदकुमार ने नए लेबर कोड को लेकर सवाल किया। विधायक ने आरोप लगाया कि इन नए नियमों से नौकरी की सुरक्षा कमजोर होगी, स्थायी रोजगार की अवधारणा को नुकसान पहुंचेगा और वेतन व काम के घंटों से जुड़े कई मौजूदा अधिकार खत्म हो सकते हैं। इसके जवाब में श्रम मंत्री शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल की परंपरा हमेशा से मजदूरों के पक्ष में रही है और राज्य सरकार किसी भी ऐसी नीति को मंजूरी नहीं देगी, जो श्रमिकों को असुरक्षित या कमजोर बनाती हो।

मंत्री ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नए श्रम सुधारों का असली मकसद मजदूरों का कल्याण नहीं, बल्कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना है। उनके अनुसार, इन लेबर

कोड के जरिए श्रमिकों की सौदेबाजी की ताकत कम की जा रही है और यूनियनों की भूमिका को सीमित करने की कोशिश हो रही है। शिवनकुट्टी ने कहा कि सामाजिक न्याय और श्रम अधिकारों की जो परिकल्पना संविधान में की गई है, नए लेबर कोड उसके विपरीत हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार नए लेबर कोड बनाए हैं, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कई मानकों पर खरे नहीं उतरते। मंत्री के मुताबिक, काम के घंटे, अनुबंध आधारित रोजगार, छंटनी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों में ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर मजदूरों की आजीविका और सुरक्षा पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि केरल सरकार इन कोड्स को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज करा रही है। शिवनकुट्टी ने सदन को यह भी बताया कि राज्य सरकार इन श्रम कोड्स के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति गठित करेगी। यह समिति नए कानूनों के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी असर का आकलन करेगी और अपनी रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि जहां कई अन्य राज्यों ने केंद्र के दबाव में अपने श्रम कानूनों में संशोधन कर लिए हैं, वहीं केरल ने साफ रुख अपनाया है कि वह किसी भी मजदूर विरोधी संशोधन को लागू नहीं करेगा।

मंत्री के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में केंद्र और केरल सरकार के बीच लेबर कोड को लेकर टकराव और तेज हो सकता है। केरल सरकार का मानना है कि विकास के नाम पर श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती और राज्य मजदूर हितों के सवाल पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। यह मुद्दा न केवल राजनीतिक बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर श्रम नीतियों को लेकर एक बड़ी बहस का संकेत भी माना जा रहा है।

भीषण गर्मी से झुलसा ऑस्ट्रेलिया, 50 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, खेल से लेकर आम जीवन तक असर

वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया इन दिनों भीषण हीटवेव की चपेट में है और देश के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लंबे समय से जारी इस गर्मी के प्रकोप ने हालात इतने गंभीर कर दिए हैं कि कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। तेज धूप, लू जैसे हालात और लगातार बढ़ते तापमान ने आम लोगों के साथ-साथ प्रशासन और आयोजनों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि बुधवार से कुछ इलाकों में तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन राहत पूरी तरह मिलने की उम्मीद कम है और सप्ताहांत तक हीटवेव का असर बने रहने की संभावना जताई गई है।

इस असहनीय गर्मी का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी और ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। विक्टोरिया राज्य के ग्रामीण कस्बों होपटून और वालपीप में शुरुआती तौर पर अधिकतम तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन के सबसे ऊंचे तापमान में से एक माना जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, लोग बेहद जरूरी कामों के अलावा घरों से निकलने से बचते नजर आए और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से जुड़ी शिकायतों में इजाफा देखा गया है। गर्मी का असर अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों पर भी साफ दिखाई दिया। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न में चल रहे प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट पर हीटवेव की मार पड़ी है। आमतौर पर दर्शकों से भरे रहने वाले स्टेडियम परिसर के बाहर मंगलवार को अपेक्षाकृत सन्नाटा देखा गया। तेज धूप और झुलसाने वाली गर्मी के चलते दर्शकों की संख्या में कमी आई और कई लोग लंबे समय तक खुले में रहने से बचते दिखे। हालात को देखते हुए टूर्नामेंट आयोजकों को 'एक्सट्रीम हीट प्रोटोकॉल' लागू करना पड़ा, जिसके तहत खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए। मैचों के दौरान ब्रेक बढ़ाए गए, खिलाड़ियों को अधिक पानी और ठंडक देने की व्यवस्था की गई और जरूरत पड़ने पर मुकाबले रोकने की भी तैयारी रखी गई। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नागरिकों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। कई इलाकों में स्कूलों और बाहरी गतिविधियों पर भी असर पड़ा है, वहीं बिजली की मांग बढ़ने से ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव महसूस किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की चरम मौसम घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और भविष्य में हीटवेव की तीव्रता और अवधि दोनों में इजाफा हो सकता है।

हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ राहत के संकेत दिए हैं, लेकिन फिलहाल देश के बड़े हिस्से को अभी और गर्मी झेलनी पड़ सकती है।

पश्चिम रेल्वे द्वारा स्पेशल ट्रेनों की ट्रिप बढ़ाइ जाएगी

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	चलाने के दिन	तक विस्तारीत
04828	बांद्रा टर्मिनस - भगत की कोठी	रविवार	01.03.2026
04827	भगत की कोठी - बांद्रा टर्मिनस	शनिवार	28.02.2026
09622	बांद्रा टर्मिनस - अजमेर	सोमवार	23.02.2026
09621	अजमेर - बांद्रा टर्मिनस	रविवार	22.02.2026
04728	वलसाड - हिसार	गुरुवार	26.02.2026
04727	हिसार - वलसाड	बुधवार	25.02.2026

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन नंबर 04828, 09622 और 04728 के बढ़ाए गए ट्रिप के लिए बुकिंग 28.01.2026 से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी।
ऊपर बताई गई ट्रेनें स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक करें और फॉलो करें:
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें।

संपादकीय

लोकतंत्र का भविष्य नागरिक चेतना और सहभागिता से ही सुरक्षित

जब भारत 77वां गणतंत्र दिवस हर्ष, गर्व और आत्मविश्वास के साथ मना रहा है, तब यह अवसर केवल उत्सव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह दिन हमें संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक दायित्वों पर गंभीरता से सोचने का अवसर भी देता है। गणतंत्र केवल शासन की एक व्यवस्था नहीं, बल्कि नागरिकों और सत्ता के बीच विश्वास, जवाबदेही और सहभागिता का जीवंत अनुबंध है। ऐसे में यह आत्ममंथन जरूरी हो जाता है कि क्या हम एक समाज के रूप में अपने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं या केवल अपेक्षाएं ही कर रहे हैं।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान उसकी संवैधानिक संस्थाओं से होती है। संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, चुनाव आयोग और स्वतंत्र मीडिया—ये सभी लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं। इन संस्थाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनपक्षधरता से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा बना रहता है। लेकिन जब प्रशासनिक प्रक्रियाएं जटिल हो जाएं, जब तंत्र जनतंत्र पर हावी होने लगे और आम नागरिक को न्याय या सुविधा पाने के लिए संघर्ष करना पड़े, तब लोकतंत्र की आत्मा को ठेस पहुंचती है। इसलिए शासन का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि नागरिकों का जीवन सरल बने और सत्ता तथा प्रशासन तक उनकी पहुंच सहज और सम्मानजनक हो। लोकतंत्र की मजबूती की जिम्मेदारी केवल सरकारों या संवैधानिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है। नागरिकों की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता है। नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाना, जनहित के मुद्दों पर आवाज बुलंद करना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहकर असहमति दर्ज कराना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इस प्रक्रिया में स्वतंत्र मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब मीडिया सत्ता के प्रति जवाबदेही तय करता है और जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता है, तब लोकतंत्र और अधिक सशक्त बनता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में समाज की सामूहिक शक्ति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि समाज में असीम ऊर्जा होती है और उसका सक्रिय समर्थन किसी भी नीति या योजना को जनआंदोलन में बदल सकता है। डिजिटल भुगतान का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि आज दुनिया के लगभग आधे डिजिटल लेन-देन भारत में होते हैं। यह उपलब्धि केवल तकनीकी प्रगति का परिणाम नहीं, बल्कि नागरिकों की भागीदारी और विश्वास का भी प्रमाण है। जब आम लोग किसी व्यवस्था को अपनाते हैं, तो वही व्यवस्था देश की ताकत बन जाती है। यही जनभागीदारी लोकतंत्र को जीवंत और गतिशील बनाए रखती है। हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस ने भी नागरिकों की भूमिका को फिर से रेखांकित किया। लोकतंत्र में मतदाता सबसे बड़ी शक्ति होता है। मतदान केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। एक जागरूक मतदाता यह समझता है कि उसका एक वोट देश की दिशा तय करने की क्षमता रखता है। भारतीय राजनीति में लंबे समय से धनबल, बाहुबल और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों का प्रभाव चिंता का विषय रहा है। लेकिन इस स्थिति को बदलने की शक्ति भी मतदाताओं के हाथ में ही है। यदि नागरिक विवेकपूर्ण मतदान करें और ईमानदार, संवेदनशील तथा समाज से जुड़े उम्मीदवारों को चुनें, तो राजनीति का चरित्र बदला जा सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। बीते वर्षों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है और कई राज्यों में सरकार गठन में उनकी भूमिका निर्णायक साबित हुई है। यह बदलाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना में आए परिवर्तन का भी द्योतक है। खेतों में काम करने वाली महिलाओं से लेकर अंतरिक्ष अभियानों में नेतृत्व करने वाली वैज्ञानिकों तक, सेना में सेवा देने से लेकर अंतरराष्ट्रीय खेलों में देश का मान बढ़ाने तक—भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस सहभागिता को और मजबूत आधार दिया जाए। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सरकारी योजनाएं तभी प्रभावी होंगी, जब वे महिलाओं के जीवन में वास्तविक और स्थायी बदलाव लाएं। जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, आवास योजनाओं में संपत्ति पर अधिकार और स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी से करोड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। इन पहलों से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक निर्णयों में उनकी भूमिका भी बढ़ी है।

दुनिया जल के वैश्विक दिवालियापन की ओर बढ़ रही है

> “दरअसल, जल संकट अब ‘वाटर स्ट्रेस’ से आगे बढ़कर ‘ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी’ यानी दुनिया जल के वैश्विक दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है। स्थिति यह है कि जल स्रोतों का दोहन इतनी तीव्रता से हो रहा है कि उनकी प्राकृतिक भरपाई असंभव होती जा रही है। भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है, नदियां सूख रही हैं और तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं।

“जल है तो जीवन है”-यह पंक्ति कोई नारा भर नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का शाश्वत सत्य है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। किंतु विडंबना यह है कि जिस जल को हम जीवन का आधार मानते हैं, वही आज सबसे अधिक संकटग्रस्त संसाधन बन चुका है। देश-दुनिया में जल संकट के हालात विकराल हो चुके हैं और यह संकट अब केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही, भ्रष्टाचार और मूल्यहीन शासन का भी परिणाम बनता जा रहा है। विश्व स्तर पर लगभग 25 देश अत्यधिक जल तनाव से जूझ रहे हैं। चार अरब से अधिक लोग वर्ष में कम से कम एक माह पानी की गंभीर कमी का सामना करते हैं। मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र इस संकट की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां 60 करोड़ से अधिक लोग उच्च जल तनाव वाले क्षेत्रों में रहते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित हैं, जबकि चेन्नई, बेंगलूरु और दिल्ली जैसे महानगरों में पानी की कमी रोजमर्रा की समस्या बन चुकी है। दरअसल, जल संकट अब ‘वाटर स्ट्रेस’ से आगे बढ़कर ‘ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी’ यानी दुनिया जल के वैश्विक दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है। स्थिति यह है कि जल स्रोतों का दोहन इतनी तीव्रता से हो रहा है कि उनकी प्राकृतिक भरपाई असंभव होती जा रही है। भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है, नदियां सूख रही हैं और तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं। यह संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकट भी है। जल संकट का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कृषि, उद्योग और ऊर्जा-तीनों ही क्षेत्र पानी पर निर्भर हैं। जब खेतों को पानी नहीं मिलता, उद्योग ठप होते हैं और बिजली उत्पादन प्रभावित होता है, तो देश की जीडीपी में 6 प्रतिशत तक की कमी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आमजन के लिए यह संकट

जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन जाता है। जहां पानी पर्याप्त है, वहां बर्बादी हो रही है और जहां पानी की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां लोग बूंद-बूंद को तरस रहे हैं।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय बनाया है। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रम इसी दिशा में ऐतिहासिक पहल हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा सके। अटल भूजल योजना भूजल के सतत प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना “हर खेत को पानी” के संकल्प को साकार करने का प्रयास है। इसके साथ ही जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। इन योजनाओं ने निश्चित रूप से जल संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत किया है। कई क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनी हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा मिला है और भूजल पुनर्भरण के प्रयास हुए हैं। लेकिन इस सकारात्मक तस्वीर के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है- प्रशासनिक भ्रष्टाचार। यही वह दीमक है जो इन योजनाओं की उपयोगिता और प्रासंगिकता को नष्ट कर रही है, उन्हें मूल्यहीन बना रही है।

जल संकट से जुड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार कई रूपों में दिखाई देता है-घटिया निर्माण, फर्जी आंकड़े, अधूरी परियोजनाएं, कमीशनखोरी और जवाबदेही का अभाव। कहीं कागजों में ही वर्षा जल संचयन संरचनाएं बन जाती हैं, तो कहीं पाइपलाइन बिछाने में घटिया सामग्री का उपयोग होता है। कई स्थानों पर योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाता। परिणाम यह होता है कि करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन न पानी मिलता है और न संकट कम होता है। भ्रष्टाचार केवल धन की बर्बादी नहीं करता, वह भविष्य की पीढ़ियों का अधिकार भी छीन लेता है। इन जटिल होती जल संकट स्थितियों के प्रति नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों को बूंद-बूंद के लिये तरसना पडेगा। जल जैसे जीवनदायी संसाधन के साथ किया गया भ्रष्टाचार वास्तव में मानवता के साथ अपराध है। जब जल संरक्षण की योजनाएं कागजों में सिमट जाती हैं, तब जल संकट और भी गहरा हो जाता है। यही कारण है कि आज योजनाएं तो हैं, नीतियां भी हैं, लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, अतिदोहन, अनियंत्रित शहरीकरण और खराब प्रबंधन इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोका गया, तालाब पाट दिए गए और जंगलों का विनाश किया गया। परिणामस्वरूप वर्षा का पैटर्न बदल गया और जल स्रोत सूखते चले गए। यह स्पष्ट है कि केवल सरकारी योजनाओं से ही समाधान संभव नहीं, जब तक समाज स्वयं जिम्मेदारी न ले।

दुनिया के अन्य देशों से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इजराइल में ड्रिप इरिगेशन और डिसेलिनेशन तकनीक से 90 प्रतिशत तक पानी का पुनर्चक्रण किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में वाटर ट्रेडिंग के माध्यम से जल संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया गया है। अमेरिका में अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और यूरोप में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जल संकट से निपटने के प्रभावी उपाय बने हैं। भारत में भी राजस्थान जैसे राज्यों में जोहड़, खादिन और बावड़ियों जैसे पारंपरिक जल संरचनाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। समाधान का रास्ता स्पष्ट है-कठोर नीतियां, पारदर्शी प्रशासन और जनभागीदारी। जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनानी होगी। तकनीक का उपयोग कर निगरानी और सामाजिक ऑडिट को अनिवार्य बनाना होगा। आमजन को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वर्षा जल संचयन, जल की बचत, ड्रिप सिंचाई और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग केवल विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता हैं।

भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र 4 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है। देश में अत्यधिक जल दोहन तथा अकुशल प्रबंधन के कारण भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। नीति आयोग के अनुसार, वर्तमान में स्वच्छ जल की अपर्याप्त पहुँच के कारण लगभग 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं तथा इसके कारण प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है। वर्ष 2030 तक देश में जल की मांग, आपूर्ति की दोगुनी होने की संभावना है। इससे देश में करोड़ों लोगों को जल के गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा तथा देश के सकल घरेलु उत्पाद में 6 प्रतिशत की हानि होने की संभावना है। आज समय बहुत कम है। यदि अभी भी हम नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। जल का संकट केवल वर्तमान का नहीं, भविष्य का प्रश्न है। जल है तो जीवन है-इस सत्य को हमें व्यवहार में उतारना होगा। भ्रष्टाचार मुक्त जल प्रबंधन, जिम्मेदार प्रशासन और जागरूक नागरिक ही हमें इस ‘जल-संकट’ से बचा सकते हैं। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब इतिहास गवाह बनेगा कि मानव ने अपने ही हाथों से जीवन के स्रोत को नष्ट कर दिया। भू-जल प्रबंधन, कुशल सिंचाई प्रबंधन एवं वर्षा जल संचयन उपायों को अपनाकर भविष्य के जल संकट को कम किया जा सकता है।

प्रेरणा

वीरता से ऊपर मानवता का मूल्य

इतिहास में युद्धों, विजयों और पराजयों की असंख्य कथाएँ दर्ज हैं। अधिकांश कथाएँ शक्ति, रणनीति और साहस की प्रशंसा करती हैं, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे भी होते हैं जो यह याद दिलाते हैं कि सच्ची महानता केवल विजय में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की रक्षा में निहित होती है। मानवता का सम्मान वही कर सकता है, जिसके भीतर करुणा, संवेदना और नैतिक साहस हो। फ्रांस के महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ी एक घटना इसी सत्य को उजागर करती है, जो बताती है कि युद्ध के क्रूर वातावरण में भी मानवीय मूल्य जीवित रह सकते हैं।

नेपोलियन बोनापार्ट अपने समय के सबसे शक्तिशाली और कुशल सैन्य नेताओं में गिने जाते हैं। उनके विजय अभियानों ने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया था। कई राज्यों को पराजित करने के बाद भी नेपोलियन का तरीका अन्य विजेताओं से अलग था। वे अक्सर पराजित राजाओं से वफादारी का आश्वासन लेकर उनका राज्य उन्हें वापस सौंप देते थे। यह नीति केवल राजनीतिक चतुराई नहीं थी, बल्कि उसमें यह विश्वास भी निहित था कि स्थायी शासन भय से नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास से चलता है। ऐसी ही एक घटना में नेपोलियन ने एक पराजित राजा को उसका राज्य पुनः लौटा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश, उस राजा ने नेपोलियन के विश्वास को तोड़ा और शत्रुओं से जा मिला। उसने नेपोलियन के विरुद्ध विद्रोह का मार्ग चुना। यह विश्वासघात किसी भी विजेता को क्रोधित करने के लिए पर्याप्त था। नेपोलियन ने भी इसे अपने सम्मान और सत्ता को दी गई चुनौती के रूप में लिया और उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करने का निर्णय किया। नेपोलियन की विशाल और अनुशासित सेना जैसे ही राजधानी की ओर बढ़ी, भय का माहौल फैल गया। राजा अपने परिवार के साथ जान बचाने के लिए जंगलों की ओर भाग गया। लेकिन हड़बड़ी और अफरातफरी में एक दुखद भूल हो गई। राजा का एक बीमार राजकुमार महल में ही छूट गया। युद्ध की तैयारी के बीच किसी को उसकी याद नहीं रही। राजधानी पर तोपें तैनात थीं और नेपोलियन ने राजमहल को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। तोपों की गर्जना से आकाश कांप उठा। युद्ध का वह दृश्य पूरी तरह क्रूर और भयावह था। इसी बीच, महल के भीतर बीमार राजकुमार गोलाबारी से भयभीत होकर इधर-उधर दौड़ने लगा। उसकी कमजोरी और असहाय अवस्था उसे बचने का कोई मार्ग नहीं दे रही थी। किसी तरह सैनिकों को यह जानकारी मिली कि महल के अंदर एक बीमार बालक फंसा हुआ है। यह समाचार तुरंत नेपोलियन तक पहुंचाया गया। यहाँ इतिहास का वह क्षण आता है, जो नेपोलियन को केवल एक विजेता सेनापति नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में स्थापित करता है। जैसे ही नेपोलियन को यह पता चला कि महल के भीतर एक निर्दोष और बीमार राजकुमार मौजूद है, उन्होंने बिना किसी हिचक के तुरंत गोलाबारी रुकवा दी। युद्ध की गूंज अचानक शांत हो गई। तोपें थम गईं और सैनिक स्तब्ध रह गए। तोपों की आवाज थमते ही एक सेनापति ने नेपोलियन के पास आकर विरोध जताया। उसने कहा कि इस निर्णय से सैनिकों का उत्साह टूट गया है और यह युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन है। उसके अनुसार, शत्रु की राजधानी पर हमला रोकना रणनीतिक दृष्टि से गलत था। यह वह क्षण था, जब नेपोलियन को एक सेनानायक के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में उत्तर देना था। नेपोलियन का उत्तर इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, “मेरे भाई, मैं मानता हूं कि सैनिकों के नियमों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन यदि गोलाबारी जारी रहती तो मानवता का भी अपमान होता। और यह हम वीरों को शोभा नहीं देता।” इस एक वाक्य में नेपोलियन ने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए युद्ध के नियमों से ऊपर मानव जीवन का मूल्य है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तविक वीरता क्या होती है। क्या केवल शत्रु को परास्त करना ही वीरता है, या संकट के समय करुणा दिखाना भी उतना ही बड़ा साहस है? युद्ध का मैदान आमतौर पर निर्दयता और क्रूरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन नेपोलियन का यह निर्णय साबित करता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक विवेक को जीवित रखा जा सकता है। मानवता का सम्मान केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में समान रूप से लागू होता है। सत्ता, शक्ति और सफलता जब संवेदना से विहीन हो जाती हैं, तो वे विनाश का कारण बनती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन शासकों और नेताओं ने केवल शक्ति के बल पर शासन किया, वे लंबे समय तक स्मरणीय नहीं रहे। इसके विपरीत, वे लोग जो अपने निर्णयों में मानवीय मूल्यों को स्थान देते हैं, सदियों तक प्रेरणा बने रहते हैं। आज के समय में, जब दुनिया संघर्ष, हिंसा और असहिष्णुता से जूझ रही है, यह घटना और भी प्रासंगिक हो जाती है। राष्ट्रों के बीच युद्ध हों या समाज के भीतर टकराव, यदि मानवता को पीछे छोड़ दिया जाए तो कोई भी विजय स्थायी नहीं हो सकती। निर्दोषों की रक्षा करना, कमजोर की आवाज सुनना और करुणा को प्राथमिकता देना ही सभ्य समाज की पहचान है। नेपोलियन का उदाहरण यह भी सिखाता है कि नेतृत्व का वास्तविक अर्थ क्या है। एक सच्चा नेता वही होता है जो केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि नैतिक दिशा दिखाने वाला भी हो। जब सेनापति मानवता का सम्मान करता है, तो उसके सैनिक भी केवल योद्धा नहीं, बल्कि जिम्मेदार मनुष्य बनते हैं। ऐसा नेतृत्व ही समाज और राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाता है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मानवता का सम्मान किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं है। अक्सर करुणा को दुर्बलता समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में करुणा दिखाने के लिए अपार आत्मबल और साहस की आवश्यकता होती है। युद्ध के बीच गोलाबारी रोकना आसान निर्णय नहीं था, लेकिन नेपोलियन ने यह साबित किया कि नैतिक साहस शारीरिक शक्ति से कहीं बड़ा होता है।

देश की प्रगति पर ब्रेक लगा रहा है ट्रैफिक जाम

देश आधारभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। हर तरफ हाल—बेहाल है। देश के राजनीतिक दल ऐसी सुविधाएं के प्रति गंभीर नहीं हैं। यही वजह है कि इन सुविधाओं की कमी से देश का हर साल अरबों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजनीतिक दल और सरकारें ऐसी सुविधाओं की कमी के लिए एक—दूसरे को कोस कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के अनुसार बेंगलुरु दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा जाम वाला शहर है। रैंकिंग में सिर्फ मैक्सिको सिटी ऐसा शहर है, जहां ट्रैफिक की स्पीड बेंगलुरु से कम है। पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र का पुणे शहर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेंगलुरु के जाम के कारण लोगों को एक साल में 168 घंटे गंवाने पड़े। यह समय 7 दिन और 40 मिनट के बराबर है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीएजी) के सर्वे के अनुसार, सुबह 7 से 9 और शाम को 6 से 8 को पीक समय माना गया है। इस दौरान आने-जाने में औसत से डेढ़ गुना अधिक समय लगता है। इस सर्वे में कोलकाता की स्थिति सबसे खराब थी। बेंगलुरु दूसरे पायदान पर रहा। सबसे ज्यादा वाहनों की संख्या के बावजूद बेहतर सड़कों के चलते दिल्ली की स्थिति बेहतर रही। रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली में निजी वाहन से चलने वालों की संख्या सबसे अधिक 45 फीसदी रही, जबकि बेंगलुरु में यह आंकड़ा 38 फीसदी रहा। सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग के मामले में मुंबई ने बाजी मारी, जिसके बाद कोलकाता का नंबर रहा। इस मामले में बेगलुरू सबसे निचले पायदान पर रहा जहां ट्रैफिक जाम आम हो गया है।

भारत के प्रमुख चार शहरों- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में ट्रैफिक जाम के चलते हर साल 1.47 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होता है। एक हालिया स्टडी में खुलासा हुआ है कि ट्रैफिक जाम के कारण बेंगलुरु को लगभग हर साल 20,000 करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान होता है। भारत की सिलिकॉन वैली का सपना देखने वाले इस शहर में हर साल हजारों लोग आते हैं। पिछले 15 सालों में शहर की आबादी तेजी से बढ़ी है। अब यहां करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। सड़कों पर एक करोड़ से अधिक गाड़ियां हैं। गाड़ियों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक बयान में कहा था कि साल 2027 तक शहर में वाहनों की संख्या यहां की आबादी से ज्यादा होगी।

दिल्ली में यातायात जाम से संबंधित आर्थिक नुकसान 2030 तक 14.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अकेले यातायात जाम के कारण ईंधन की बर्बादी से प्रतिदिन लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिससे शहर में पहले से ही गंभीर वायु गुणवत्ता की समस्या और भी बढ़ जाएगी। रपिोर्ट में पता चला कि कर्मचारियों ने काफी समय ट्रैफिक में फंसकर बिताया, जिससे उत्पादकता में काफी नुकसान हुआ। स्टडी का अनुमान है कि ट्रैफिक संबंधी बाधाओं के कारण अकेले आईटी सेक्टर को लगभग 7,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा, छोटे और मध्यम उद्यमों पर ट्रैफिक जाम के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। ये व्यवसाय डिलीवरी शेड्यूल को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिपमेंट में देरी होती है और ग्राहक असंतुष्ट होते हैं। बदले में इसका शहर की अर्थव्यवस्था पर तेजी से प्रभाव पड़ता है, जिससे लगभग 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

भारत में वर्ष 2000 से मोटर वाहन उपयोग में भारी वृद्धि हुई है और हर 5-6 वर्षों में नए वाहनों की संख्या दोगुनी हो जाती है। हालांकि महामारी के कारण कुछ समय के लिए यह वृद्धि रुक गई, लेकिन मोटर वाहन उपयोग में तेजी से सुधार हुआ और 2023-24 में औसतन प्रतिदिन 58,000 नए वाहन पंजीकृत हुए, जिनमें से 52,000 निजी वाहन थे। दिल्ली में, इसी अवधि में औसतन 6.4 लाख वाहन पंजीकृत हुए और औसतन प्रतिदिन नए वाहन पंजीकृत हुए, जिनमें से लगभग 1,750 नए वाहन थे। यातायात जाम बढ़ने का एक कारण ‘कारों की अत्यधिक संख्या’ है।

ट्रैफिक में वाहनों के खड़े रहने से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 3% बर्बाद हो जाता है। महानगर यातायात के कारण जाम से ग्रस्त हो गए हैं, जिसका 10% ईंधन की खपत के कारण बर्बाद होता है। जहां वाहन ट्रैफिक में खड़े होते हैं, वहां प्रदूषण का एक क्षेत्र बन जाता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। यातायात जाम का प्रदूषण पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रुके हुए वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन सुचारू रूप से चल रहे यातायात की तुलना में 3 से 7 गुना अधिक हो सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा उत्सर्जित होती है, जिससे स्थानीय वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की शहरी जनसंख्या 31.16% थी, जो विश्व बैंक के 2022 के अनुमान के अनुसार शहरी जनसंख्या 2020 तक बढ़कर 35% हो चुकी है। शहरीकरण की यह गति आने वाले वर्षों में और तेज होगी, जिससे महानगरों में वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी। दिल्ली में 2023 तक लगभग 1.2-1.3 करोड़ पंजीकृत वाहन थे,

पर्यावरण प्रदूषण भी ट्रैफिक जाम की एक गंभीर परिणति है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं। ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन में भारी वृद्धि होती है, जिससे वायु गुणवत्ता खराब होती है और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रभावी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना अनिवार्य है। अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क, इलेक्ट्रिक बसों और साइकिल ट्रैक को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में हाई-ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे एक से अधिक यात्रियों वाले वाहनों को प्राथमिकता मिले और कार-पूलिंग को प्रोत्साहन मिले।

अभियान

आस्था के मार्ग पर 21 दिन: प्रेमानंद महाराज द्वारा बताए श्रीकृष्ण मंत्र से जीवन परिवर्तन की साधना

सनातन परंपरा में मंत्रों को केवल उच्चारित किए जाने वाले शब्द नहीं माना गया, बल्कि उन्हें चेतना को दिशा देने वाली दिव्य शक्ति के रूप में देखा गया है। मंत्र वह सेतु है, जो सीमित मनुष्य को असीम ब्रह्म से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, नियम और निरंतरता के साथ मंत्र साधना करता है, तब उसके जीवन में सूक्ष्म लेकिन गहरे परिवर्तन होने लगते हैं। आज के समय में, जब मनुष्य मानसिक तनाव, भय, अस्थिरता, पारिवारिक कलह और जीवन की अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भक्ति और साधना ही वह आधार बनती है, जो उसे भीतर से संभालती है। इसी संदर्भ में वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए भगवान श्रीकृष्ण के एक विशेष मंत्र की चर्चा अत्यंत प्रासंगिक और प्रभावशाली मानी जाती है।

प्रेमानंद महाराज का जीवन स्वयं भक्ति, तप और साधना का उदाहरण है। वे मानते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण आज भी उतने ही जीवंत हैं, जितने द्वापर युग में थे। अंतर केवल भक्त की भावना और समर्पण का है। महाराज के अनुसार, श्रीकृष्ण को पाने के लिए कठिन तप या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे हृदय से किया गया नाम स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐसे मंत्र की साधना का मार्ग बताया है, जिसे यदि 21 दिनों तक नियमपूर्वक किया जाए, तो साधक के जीवन में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर गहरा परिवर्तन देखने को मिलता है।

महाराज बताते हैं कि आज का मनुष्य बाहरी समस्याओं से अधिक आंतरिक अशांति से पीड़ित है। धन, पद, सुविधा और तकनीक के बावजूद मन शांत नहीं है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने जीवन के केंद्र से दूर हो गया है। वह स्वयं को परिस्थितियों के हवाले कर चुका है। श्रीकृष्ण मंत्र साधना का उद्देश्य साधक को फिर से उसके केंद्र में लौटाना है, जहां से वह जीवन को संतुलित दृष्टि से देख सके।

प्रेमानंद महाराज द्वारा बताया गया मंत्र है—

“ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः॥”

यह मंत्र अपने भीतर श्रीकृष्ण तत्व की संपूर्णता को समेटे हुए है। इसमें भगवान के विभिन्न नामों के माध्यम से उनके अनेक स्वरूपों का स्मरण किया गया है। ‘कृष्ण’ वह शक्ति है, जो आकर्षण और आनंद का मूल है। ‘वासुदेव’ भगवान के अवतार स्वरूप को दर्शाता है, जो मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ। ‘हरि’ उस तत्व का प्रतीक है, जो भक्तों के दुख, पाप और भय को हर लेता है। ‘परमात्मा’ यह संकेत देता है कि श्रीकृष्ण केवल एक रूप या कथा तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि में व्याप्त चेतना हैं। ‘गोविंद’ नाम से यह भाव प्रकट होता है कि वही इस संसार का पालन और संरक्षण करने वाले हैं।

इस मंत्र का भावार्थ साधक को पूर्ण शरणागति की भावना में ले जाता है। इसका अर्थ है कि मैं भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में नमन करता हूं, जो मेरे सभी क्लेशों का नाश करने वाले हैं। यह भाव साधक के भीतर बैठे अहंकार को धीरे-धीरे गलाने लगता है। जब अहंकार कम होता है, तब मन हल्का होता है और वही हल्कापन शांति का द्वार खोलता है।

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इस मंत्र का सबसे पहला प्रभाव मन पर पड़ता है। जो लोग निरंतर चिंता, भय, नकारात्मक विचारों या मानसिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, उन्हें 21 दिनों की साधना के भीतर ही परिवर्तन का अनुभव होने लगता है। मन की चंचलता धीरे-धीरे कम होती है। विचारों की भीड़ शांत होने लगती है। साधक यह अनुभव करता है कि समस्याएं वैसी ही हैं, लेकिन उनसे निपटने की उसकी क्षमता बढ़ गई है। यही वास्तविक परिवर्तन है।

इस मंत्र की साधना केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह साधक की चेतना को भी ऊपर उठाती है। महाराज बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से श्रीकृष्ण का नाम स्मरण करता है, तो उसके भीतर एक सुरक्षा भाव जाग्रत होता है। उसे यह अनुभूति होने लगती है कि वह अकेला नहीं है। श्रीकृष्ण हर क्षण उसके साथ हैं। यही अनुभूति जीवन के सबसे बड़े भय—असुरक्षा—को समाप्त करती है। जब भय समाप्त होता है, तब जीवन की कठिनाइयां भी अपना डर खो देती हैं।

पारिवारिक जीवन में इस मंत्र का प्रभाव विशेष रूप से देखा गया है। आज अधिकांश परिवारों में तनाव, संवाद की कमी और गलतफहमियां आम हो गई हैं। प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि जब घर का कोई एक सदस्य भी इस मंत्र की साधना करता है और उसके व्यवहार में शांति और धैर्य आता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। व्यक्ति प्रतिक्रिया देना छोड़कर समझदारी से उत्तर देने लगता है। यही परिवर्तन रिश्तों को जोड़ने लगता है। धीरे-धीरे घर का वातावरण भी सौम्य और सकारात्मक होने लगता है।

महाराज यह स्पष्ट करते हैं कि इस मंत्र को किसी चमत्कारिक उपाय की तरह नहीं देखना चाहिए। यह कोई ऐसा साधन नहीं है, जो बिना प्रयास के सब कुछ बदल दे। यह एक अनुशासन है, जो साधक से ईमानदारी और निरंतरता की मांग करता है। साधना के लिए प्रातः काल या सायंकाल का समय श्रेष्ठ माना गया है, जब वातावरण स्वाभाविक रूप से शांत होता है। स्थान स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। साधक को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि बाहरी और भीतरी शुद्धि दोनों बनी रहें।

तुलसी माला से मंत्र जाप करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि तुलसी भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। कम से कम 108 बार मंत्र जाप करना उत्तम माना गया है। जाप से पहले साधक को मन ही मन यह संकल्प लेना चाहिए कि वह 21 दिनों तक इस साधना को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेगा। संकल्प साधना को स्थिरता देता है और साधक को बीच में भटकने से बचाता है।

प्रेमानंद महाराज यह भी कहते हैं कि साधना के दौरान धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कई लोग कुछ ही दिनों में परिणाम देखने की अपेक्षा करते हैं और जब तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, तो निराश हो जाते हैं। महाराज बताते हैं कि यह मंत्र बाहर से पहले भीतर काम करता है। भीतर होने वाला परिवर्तन ही आगे चलकर जीवन की परिस्थितियों को बदलता है। इसलिए साधक को परिणाम के प्रति नहीं, बल्कि प्रक्रिया के प्रति समर्पित रहना चाहिए।

इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह साधक को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी ने 'स्वतंत्रता का मंत्र : वंदे मातरम' विषय पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की निर्माण यात्रा, उसके बदलते स्वरूप और इतिहास की रोचक प्रस्तुति के साथ जमाया अनूठा आकर्षण

▸▸ सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला ने सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कर गुजरात को गौरवान्वित किया

▸▸ 77वें गणतंत्र पर्व में इस वर्ष पहली बार 'साइलेंट वॉरियर्स' के रूप में पहचाने जाने वाले पशुओं ने भी परेड में हिस्सा लिया

नई दिल्ली : 'वंदे मातरम' एक मंत्र है, जो हर भारतीय में स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्रता की अलख जगाता है। 'वंदे मातरम' गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, इस विषय के प्रतिघोष के रूप में 'वंदे मातरम' शब्द की पृष्ठभूमि से ही शुरू हुई भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बनने की यात्रा, उसका बदलता स्वरूप और इतिहास की रोचक प्रस्तुति 77वें गणतंत्र दिवस पर्व में गुजरात की झांकी का प्रमुख आकर्षण बना। इसके साथ ही, इस झांकी ने गुजरात के नवसारी में जन्मी तथा गुर्जर भूमि के अपने प्रसिद्ध साथी क्रांतिवीरों- श्यामजी कृष्ण वर्मा और सरदार सिंह राणा के साथ विदेशी धरती से क्रांतिज्योत जगाने वालीं मैडम भीकाजी कामा द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज की यशोगाथा का वर्णन, जिस पर 'वंदे मातरम' लिखा है और 'चरखे' के माध्यम से स्वदेशी का मंत्र देने वाले महात्मा गांधी की स्मृति के साथ मौजूदा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के सुंदर समन्वय के माध्यम से एक अनूठी छाप छोड़ी।

झांकी के अगले हिस्से में वीरांगना मैडम भीकाजी कामा को उनके द्वारा डिजाइन किए हुए ध्वज के साथ दर्शाया गया था, जिस पर 'वंदे मातरम' लिखा हुआ था, जिसे उन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर वर्ष 1907 में पेरिस में लहराया था। इस ध्वज को जर्मनी के स्टटगार्ट, बर्लिन की 'इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस' में भी फहराया गया था। मैडम कामा की ध्वज लहराती अर्ध-प्रतिमा के नीचे संविधान में सूचीबद्ध सभी भारतीय भाषाओं में 'वंदे मातरम' लिखा हुआ था।

झांकी के दिल यानी मध्य हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज की निर्माण यात्रा, उसके बदलते स्वरूप और इतिहास को दिखाया गया। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1906 से, जब कलकत्ता (अब कोलकाता) के पारसी बागान में क्रांतिकारियों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाने और स्वदेशी का आह्वान करते हुए पहली बार 'वंदे मातरम' लिखा हुआ ध्वज फहराया था। इसके बाद, 1907 में विदेशी धरती से भारतीय क्रांति की ज्योति जगाने वाली मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में ध्वज फहराया था, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। वर्ष 1917 में होमरूल आंदोलन के दौरान डॉ. एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक नया ध्वज फहराया। वहीं, वर्ष 1921 में बेजवाड़ा (अब विजयवाड़ा) में युवा क्रांतिवीर पिंगली वेंकैया ने एक नई डिजाइन का ध्वज बनाया और उसे गांधी जी को दिखाया। 1931 में पिंगली द्वारा तैयार किए गए ध्वज को लगभग स्वीकृति दे दी गई, जो तीन रंगों का बना था और उसके केंद्र में चरखा था। अंततः 22 जुलाई, 1947 को भारतीय संविधान सभा ने झंडे के केंद्र में चरखे की जगह धर्म चक्र के साथ तिरंगे को इसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की इस निर्माण यात्रा के साथ भारत की आजादी के महत्वपूर्ण आंदोलनों का भी इस झांकी में निदर्शन किया गया।

झांकी के अंतिम हिस्से में 'चरखे' के माध्यम से स्वदेशी और स्वावलंबन की भावना को जागृत करने तथा स्वतंत्रता का आह्वान करने वाले महात्मा गांधी के शिल्प को एक विशाल धर्म चक्र के साथ दर्शाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान में स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के इन सशक्त मूल्यों को लगातार प्रोत्साहित करने का प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को याद कर राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले, 'राष्ट्रीय शायर' की उपाधि से सम्मानित गुजराती रचनाकार झवेरचंद मेघाणी द्वारा रचित गीत 'कसुंबी नो रंग' की लय और ताल पर उत्साह बढ़ाते कलाकार झांकी को जीवंत और जानदार बना रहे थे।

गुजरात सरकार के सूचना विभाग की ओर से प्रस्तुत इस झांकी के निर्माण में सूचना एवं प्रसारण सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सूचना आयुक्त श्री किशोर बचाणी, अपर निदेशक श्री अरविंद पटेल के मार्गदर्शन में संयुक्त सूचना निदेशक डॉ. संजय कचोट और उप सूचना निदेशक सुश्री भावना वसावा ने योगदान दिया।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की 13 झांकियों सहित कुल 30 झांकियां प्रदर्शित की गईं। कर्तव्य पथ पर हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में लगभग 2500 कलाकारों ने हिस्सा लिया। देश भर से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था।

परेड की शुरुआत 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' में एक गौरवपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ हुई, जहां प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद, राष्ट्रपति सलामी मंच पर पहुंचीं और राष्ट्रगान हुआ तथा 21 तोपों की सलामी के साथ समारोह की औपचारिक शुरुआत हुई। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन यूनियन के दो वरिष्ठ नेता- यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मौजूद रहे।

77वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष पहली बार 'साइलेंट वॉरियर्स' के रूप में पहचाने जाने वाले पशुओं ने भी परेड में हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत मंगोलियन प्रजाति के बेक्ट्रियन ऊंट, सियाचिन ग्लेशियर में काम करने वाले खच्चर, शिकारी पक्षी और सैन्य श्वान दस्ते सलामी मंच के सामने से गुजरे।

सेना के विभिन्न अंगों के करतबों के साथ इस वर्ष पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व 26 वर्षीय सहायक कमांडेंट सिमरन बाला ने किया। गुजरात में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली सिमरन ने गांधीनगर के सरकारी महिला कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके साथ ही, यूरोपियन यूनियन की टुकड़ी ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। इस वर्ष की परेड में पहली बार भारतीय सेना ने रणभूमि व्यूह रचना यानी 'बैटल एरे' फॉर्मेट की झलक दिखाई, जिसमें परंपरागत मार्चिंग दस्ते और सेवा प्रस्तुतियां शामिल थीं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दी 77वें गणतंत्र दिवस पर राज्य की नगर पालिकाओं को बड़ी भेंट

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य की नगर पालिकाओं को 11 प्रकार की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के लिए नि:शुल्क सरकारी भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय

▸▸ विकास कार्यों के लिए पहले सरकारी भूमि प्राप्त करने पर बाजार मूल्य या जंत्री दर के 25 से 50 प्रतिशत तक जो राशि चुकानी पड़ती थी, उससे अब मुक्ति मिलेगी

▸▸ राज्य की 152 नगर पालिकाओं पर आर्थिक भार कम होने से नागरिक सेवान्मुखी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नगरों शहरों में सार्वजनिक जनहितकारी परियोजनाओं के लिए नगरपालिकाओं को निःशुल्क भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शहरी क्षेत्रों में प्रशासन अधिक पारदर्शी बने और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं समय पर मिलें, इसके लिए नगर पालिकाओं को विकास कार्यों हेतु अब 11 प्रकार की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरलता से निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की लगभग 152 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए पहले सरकारी भूमि प्राप्त करने पर बाजार मूल्य या जंत्री दर के 25 से 50 प्रतिशत तक जो राशि चुकानी पड़ती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी अधिक सरल बनेगी।

मुख्यमंत्री द्वारा नगर पालिकाओं को सार्वजनिक सुविधा एवं जनकल्याण के परियोजनाओं के लिए निःशुल्क सरकारी भूमि देने के निर्णय के अनुसार; नगर सेवा सदन, फायर स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, भूमिगत सीवर, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, जल आपूर्ति परियोजना, सॉलिड व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज कार्य, आंगनवाड़ी, टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल, कन्वेंशन सेंटर जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हों; ऐसा सिटीजन-सेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की 152 नगर पालिकाओं पर आर्थिक भार कम होने से विकास परियोजनाएं तेजी से शुरू हो सकेंगी और नगरों के विकास को और अधिक गति मिलेगी। नागरिकों को भी पानी, सीवर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी प्राथमिक सुविधाएं शीघ्रता से उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य की नगर पालिकाओं को 11 प्रकार की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के लिए निःशुल्क सरकारी भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय

▸▸ विकास कार्यों के लिए पहले सरकारी भूमि प्राप्त करने पर बाजार मूल्य या जंत्री दर के 25 से 50 प्रतिशत तक जो राशि चुकानी पड़ती थी, उससे अब मुक्ति मिलेगी

▸▸ राज्य की 152 नगर पालिकाओं पर आर्थिक भार कम होने से नागरिक सेवान्मुखी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नगरों शहरों में सार्वजनिक जनहितकारी परियोजनाओं के लिए नगरपालिकाओं को निःशुल्क भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

शहरी क्षेत्रों में प्रशासन अधिक पारदर्शी बने और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं समय पर मिलें, इसके लिए नगर पालिकाओं को विकास कार्यों हेतु अब 11 प्रकार की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरलता से निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की लगभग 152 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए पहले सरकारी भूमि प्राप्त करने पर बाजार मूल्य या जंत्री दर के 25 से 50 प्रतिशत तक जो राशि चुकानी पड़ती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी अधिक सरल बनेगी।

मुख्यमंत्री द्वारा नगर पालिकाओं को सार्वजनिक सुविधा एवं जनकल्याण के परियोजनाओं के लिए निःशुल्क सरकारी भूमि देने के निर्णय के अनुसार; नगर सेवा सदन, फायर स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, भूमिगत सीवर, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, जल आपूर्ति परियोजना, सॉलिड व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज कार्य, आंगनवाड़ी, टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल, कन्वेंशन सेंटर जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हों; ऐसा सिटीजन-सेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की लगभग 152 नगर पालिकाओं पर आर्थिक भार कम होने से विकास परियोजनाएं तेजी से शुरू हो सकेंगी और नगरों के विकास को और अधिक गति मिलेगी।

नागरिकों को भी पानी, सीवर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी प्राथमिक सुविधाएं शीघ्रता से उपलब्ध होंगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से 03 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09622/09621 बांद्रा टर्मिनस – अजमेर (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस–अजमेर स्पेशल को 23 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09621 अजमेर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 22 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
2. ट्रेन संख्या 04828/04827 बांद्रा टर्मिनस – भगत की कोठी (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस – भगत की कोठी स्पेशल को 01 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 28 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

3. ट्रेन संख्या 04728/04727 वलसाड – हिसार (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन संख्या 04728 वलसाड – हिसार स्पेशल को 26 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04727 हिसार – वलसाड स्पेशल को 25 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09622, 04828 एवं 04728 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 28 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

77वें गणतंत्र पर्व का राज्य स्तरीय समारोह : नवगठित वाव-थराद जिले के लिए गौरवशाली क्षण

▸▸ राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने फहराया तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और विस अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी की प्रेरक उपस्थिति : ध्वज वंदन समारोह की भव्यता एवं गरिमा और बढ़ी

▸▸ मार्च पास्ट, श्वान एवं अश्व शो सहित जवानों के हैरतअंगेज करतब देख प्रेक्षक हुए रोमांचित

▸▸ थराद के मलुपुर परेड ग्राउंड में विशाल जनसमूह के बीच वायु सेना के विमानों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगे को दिया विशेष सम्मान

गांधीनगर : विकास, विश्वास और विरासत का प्रतीक वाव-थराद जिले में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। थराद के मलुपुर परेड ग्राउंड में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा और भव्यता को और बढ़ा दिया।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। उनके साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। वायु सेना के हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा कर तिरंगे की आन, बान और शान को उजागर किया। परेड मार्च पास्ट के माध्यम से शौर्य और समर्पण को उजागर करते पुलिस जवानों की विभिन्न 22 टुकड़ियों में शामिल कुल 810 जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।

राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और सलामी

देशभक्ति के उत्साह और उमंग से सराबोर वातावरण के बीच गुजरात की विकासगाथा को अविरत आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी सहित समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, समाज के अग्रणियों, अतिथियों, युवा पीढ़ी, महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने देशभक्ति के जोश के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। हर्ष ध्वनि ने राष्ट्रीय पर्व को और सुंदर बनाकर माहौल को देशभक्तिपूर्ण बना दिया।

मार्च पास्ट

पुलिस बैंड की समधुर धुनों के साथ पुलिस के जवानों की अनुशासनबद्ध परेड और मार्च-पास्ट आयोजित हुई। चेतक कमांडो, मरीन कमांडो, एसआरपी जवानों, पुलिस की विभिन्न महिला और पुरुष टुकड़ियों, एसपीसी, सैनिक स्कूल, एनसीसी और एनएसएस के कैडेटों की इस परेड का उपस्थित सभी लोगों ने आनंद उठाया।

इसके अलावा, चेतक कमांडो के बुलेटप्रूफ वाहनों के निदर्शन (टेब्लो), हैरतअंगेज मोटरसाइकिल स्टंट शो तथा राज्य के गौरव गुजरात श्वान दल, गुजरात अश्व दल के सुंदर करतबों ने हर किसी को रोमांचित कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग द्वारा राज्यों के विभिन्न परंपरागत नृत्यों की प्रस्तुति के साथ वीर रस से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। स्कूली छात्रों ने अलग-अलग थीमों पर आधारित प्रस्तुतियां दीं।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मण्डल रेल प्रबंधक ने किया औचक निरीक्षण, स्वछता पर विशेष ज़ोर

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न "स्वच्छता ही सेवा" देश को स्वच्छ, स्वस्थ एवं जागरूक बनाने के संकल्प को साकार करते हुए मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने 26 जनवरी 2026 को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड, साबरमती में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, गणतंत्र दिवस समारोह के उपरांत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने 4-5 घंटे तक स्टेशन परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का गहनता निरीक्षण किया तथा यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंडल रेल प्रबंधक ने प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, प्रतीक्षालय, शौचालय, फुटओवर ब्रिज तथा अन्य स्थलों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी क्लीनिंग स्टाफ एवं सुपरवाइजरों के साथ बैठक कर स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे सफाई करने का तरीका,कौनसी मशीन का किस तरह एवं किस जगह उपयोग करना है आदि पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कचरा निस्तारण, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, नियमित मॉनिटरिंग तथा स्वच्छता मानकों के पालन पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित किया जाए।

इसके उपरांत मंडल रेल प्रबंधक ने पार्सल कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां कार्यरत स्टाफ से पार्सल हैंडलिंग, बुकिंग, लोडिंग-अनलोडिंग तथा रिकॉर्ड संधारण की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा समयबद्ध और सुव्यवस्थित कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक सुधारात्मक सुझाव एवं निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होने मेकेनिकल एवं कमर्शियल विभाग के अधिकारियों, सुपरवाइजरों एवं कर्मचारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया एवं यातायात व्यवस्था का भी अवलोकन किया। उन्होंने यात्रियों एवं आम नागरिकों की सुविधा के लिए यातायात के सुचारु प्रवाह, पार्किंग प्रबंधन तथा ऑटो-टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कोसंबा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के सूरत–वडोदरा सेक्शन में स्थित कोसंबा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 28 जनवरी 2026 (बुधवार) को कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। जिसका विवरण इस प्रकार है:

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

1. ट्रेन नं 59049 वलसाड - वडोदरा पैसेंजर ट्रेन 28 जनवरी को रद्द रहेगी
2. ट्रेन नं 59050 वडोदरा - वलसाड पैसेंजर ट्रेन 28 जनवरी को रद्द रहेगी
3. ट्रेन नं 69150 भरूच – सूरत मेमू ट्रेन 28 जनवरी को रद्द रहेगी

आंशिक रूप से रद्द

1. 28 जनवरी 2026 को ट्रेन नं 19101 विरार – भरूच एक्सप्रेस ट्रेन सूरत तक चलेगी तथा सूरत – भरूच के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अहमदाबाद मंडल पर 77वां गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया,डीआरएम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया,उत्कृष्ट रेलकर्मियों एवं बच्चों को किया सम्मानित

पहली तस्वीर में मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। दूसरी तस्वीर में गणतंत्र दिवस संदेश वाचन करते हुए तथा अंतिम तस्वीर में रेलवे क्रिकेट ग्राउंड,साबरमती में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सामारोहिक परेड का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने अहमदाबाद स्थित रेलवे क्रिकेट ग्राउंड, साबरमती में राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं रेल सुरक्षा बल,भारत स्काउट व गाइड व सिविल डिफ़ेंस यूनिटों की सयुंक्त परेड का निरीक्षण किया और मार्च-पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक,अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने सभी रेल कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा गणतंत्र दिवस के संदेश का वाचन किया।

इस दौरान मण्डल रेल प्रबंधक ने पश्चिम रेलवे की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि रेल एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में इस वित्तीय वर्ष में 85 रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज तथा 14 फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) चालू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक कवच (KAVACH) स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हाल ही में पश्चिम रेलवे का पहला कवच सिस्टम वडोदरा–अहमदाबाद खंड के 96 रूट किलोमीटर में 17 स्टेशनों को कवर करते हुए सफलतापूर्वक चालू किया गया है, जिसमें 13.7 किलोमीटर अहमदाबाद मंडल का भी शामिल है तथा अब तक 364 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम स्थापित किया है। चालू वित्त वर्ष में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। हिम्मतनगर–खेड़ब्रह्मा, विजापुर–आंबलियासण तथा आदरज मोटी–विजापुर रेल खंडों पर गेज परिवर्तन का कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है।

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा एवं पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, अहमदाबाद मंडल की सदस्याओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता 39 बच्चों को पुरस्कृत किया गया तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित दो रेल कर्मचारियों के परिजनों को 20,000–20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

फोटो कैप्शनः अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा एवं पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन,अहमदाबाद की सदस्याएं गंभीर बीमारी से ग्रसित रेलकर्मी के परिजन को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए।

इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों एवं नृत्यों ने सभी को राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत कर दिया। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 62 रेल कर्मचारियों को प्रमाण पत्र एवं मैडल प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा चार विभागों के ग्रुप को सामुहिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इसके साथ ही 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं के 15 विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस समारोह में मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री विकास गढ़वाल, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन अहमदाबाद मंडल की टीम, सभी विभागों के शाखा अधिकारी, रेल अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

वरनामा और मकरपुरा के बीच ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों को रेगुलेट किया जाएगा

सूरत-वडोदरा सेक्शन में वरनामा -मकरपुरा के बीच ब्रिज नंबर 570 के मौजूदा स्टील गर्डर्स को PSC स्लैब से बदलना हेतु अप लाइन पर 28 जनवरी एवं डाउन लाइन पर 29 जनवरी को ब्लाक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी।

वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 28 और 29 जनवरी , 2026 को प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः-

28 जनवरी को रेगुलेट होने वाली ट्रेनेंः-

1. ट्रेन संख्या 19020 हरिद्वार - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 28 जनवरी , 2026 को 1 घंटे 10 मिनट रेगुलेट होगी।
2. ट्रेन संख्या 19012 दाहोद – वलसाड एक्सप्रेस 28 जनवरी , 2026 को 1 घंटे 10 मिनट रेगुलेट होगी।
3. ट्रेन संख्या 59050 वडोदरा - वलसाड पैसेंजर 28 जनवरी , 2026 को 40 मिनट रेगुलेट होगी।

29 जनवरी को रेगुलेट होने वाली ट्रेनेंः-

1. ट्रेन संख्या 12656 पुरैची थलाइवर - अहमदाबाद सुपरफास्ट 29 जनवरी ,2026 को 1 घंटे 10 मिनट रेगुलेट होगी।
2. ट्रेन संख्या 09724 बांद्रा टर्मिनस - जयपुर स्पेशल 29 जनवरी, 2026 को 1 घंटे रेगुलेट होगी।
3. ट्रेन संख्या 12471 बांद्रा टर्मिनस - श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट 29 जनवरी , 2026 को 30 मिनट रेगुलेट होगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

संख्याः W/623/3/NIT "ई–टेण्डरिंग नोटिस" दिनांकः22.01.2026

मंडल रेल प्रबंधक मंडल कार्यालय कार्य लेखा शाखा पश्चिम रेलवे रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली निविदा के माध्यम से वेबसाइट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते हैं विवरण इस प्रकार है

क्रम सं.	ई–टेण्डरिंग संख्या और कार्य का नाम	अनुमानित लागत रु.	बयाना राशी रु.
1.	RTM-2025-26-185 Godhra -Ratlam -Providing track machine siding with allied facilities at Jekot and balance work for Limkheda siding. अनुमानित मात्रा:- As per tender schedule, कार्य समापन अवधि:- 12 Months, Similar type of work:- Any Civil Engineering Work. वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथिः– 22.01.2026, निविदा खुलने की तिथिः– 16.02.2026	₹5,01,66,194.38	₹4,00,800.00

विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

5/1/427

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

गणतंत्र दिवस के अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके दवारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह पूर्वक मनाया गया। प्रतापनगर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं रेल सुरक्षा बल ,भारत स्काउट व गाइड व सिविल डिफ़ेंस यूनिटों की सयुंक्त परेड का निरीक्षण किया और मार्च-पास्ट की सलामी ली इस अवसर पर श्री राजू भडके ने सभी रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन भी किया। मंडल रेल प्रबंधक ने रेलकर्मियो के नाम अपने सन्देश में वडोदरा मंडल की उपलब्धिया का भी जिक्र किया और रेल सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर श्री अनवर हुसैन को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा "इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस" से सम्मानित किये जाने पर बधाई दी। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस अवसर पर संरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं व सराहनीय कार्य के लिये 04 रेलकर्मियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा की अध्यक्षा डॉ कविता भडके ने निबंध/ चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता 19 प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। आरपीएफ 'डॉग स्क्वॉड' द्वारा की गयी प्रस्तुति ने भी सभी का मन मोह लिया रेलकर्मियों द्वारा देश भक्ति पर आधारित व सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। इस शुभ अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा मंडल की अध्यक्षा डॉ कविता भडके व उनकी टीम, वडोदरा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज धमीजा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री फ्रांसिस लोबो तथा रेलवे के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ रेल अधिकारी व कर्मचारी के साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री तेजराम मीना ने इस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। इसके बाद मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके व रेलवे महिला कल्याण संगठन वडोदरा मंडल की अध्यक्षा डॉ कविता भडके ने बाल मंदिर में जाकर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में बच्चो की प्रस्तुति को देखा।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से लौटी बाजार में रौनक उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद मजबूती के साथ बंद हुए सूचकांक

नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए अहम व्यापार समझौते की सकारात्मक खबरों ने घरेलू शेयर बाजार को आखिरकार सहारा दे ही दिया। पूरे दिन असमंजस और उतार-चढ़ाव के बीच झूलने के बाद बाजार ने अंतिम घंटे में जबरदस्त वापसी की और हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। शुरुआती कारोबार में वैश्विक संकेतों और मुनाफावसूली के दबाव के कारण सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला, जबकि निफ्टी ने हल्की मजबूती दिखाई, लेकिन शुरुआती बढ़त ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। पहले घंटे में बिकवाली हावी रही, जिससे निवेशकों में सतर्कता का माहौल बना रहा। हालांकि जैसे-जैसे सत्र आगे बढ़ा, भारत-ईयू व्यापार समझौते से जुड़ी उम्मीदों और चुनिंदा सेक्टरों में खरीदारी ने बाजार की दिशा बदलनी शुरू कर दी। दिन के मध्य सत्र तक बाजार कभी ऊपर तो कभी नीचे होता रहा और निवेशक किसी ठोस दिशा के इंतजार में दिखे। लेकिन आखिरी एक घंटे में बैंकिंग, मेटल, डिफेंस और एनर्जी शेयरों में आई जोरदार लिवाली ने माहौल पूरी तरह पलट दिया। इसका असर यह रहा कि सेंसेक्स 319.78 अंकों की मजबूती के साथ 81,857.48 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 126.75 अंक चढ़कर 25,175.40 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार की इस मजबूती से निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.02 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ और बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 454.58 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो निवेशकों के भरोसे में लौटती मजबूती को दर्शाता है। कारोबार के दौरान सेक्टोरल स्तर पर देखा जाए तो बैंकिंग शेयरों में मजबूती बाजार को संभालने में सबसे अहम साबित हुई। निजी और सरकारी बैंकों में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को स्थिर आधार मिला। इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी तेजी रही, जहां वैश्विक मांग में सुधार और कच्चे माल की कीमतों में स्थिरता की उम्मीदों ने निवेशकों को आकर्षित किया। डिफेंस सेक्टर के शेयरों में भी मजबूत खरीदारी दिखी, क्योंकि हाल के दिनों में इस सेक्टर को लेकर दीर्घकालिक संभावनाओं को लेकर निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। आईटी और एनर्जी शेयरों ने भी सकारात्मक रुख दिखाया और बाजार को ऊपर खींचने में योगदान दिया। दूसरी ओर ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और हेल्थकेयर सेक्टर के शेयरों में दबाव बना रहा, जहां निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आए और मुनाफावसूली को प्राथमिकता दी। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि 13 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी की बात करें तो उसके 50 में से 31 शेयर लाभ में और 19 शेयर नुकसान में बंद हुए। बड़े शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेज, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने मजबूत प्रदर्शन किया और बाजार की तेजी में अहम भूमिका निभाई। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, एटरनल और बजाज फिनसर्व जैसे शेयरों में कमजोरी देखने को मिली, जिसने तेजी की रफ्तार को कुछ हद तक सीमित रखा। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में कमजोरी का रुख बना रहा। कई मिड और स्मॉलकैप शेयरों में निवेशकों ने जोखिम से बचने की रणनीति अपनाई, जिससे इन सेगमेंट में दबाव देखने को मिला।

कस्तूरी मेटल कंपोजिट का आईपीओ निवेशकों के लिए खुला, तीन फरवरी को SME प्लेटफॉर्म पर संभावित लिस्टिंग

नई दिल्ली। स्टील फाइबर उत्पादों के निर्माण से जुड़ी कस्तूरी मेटल कंपोजिट लिमिटेड ने पूंजी बाजार में कदम रखते हुए मंगलवार से अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) सब्सक्रिप्शन के लिए खोल दिया है। कंपनी इस इश्यू के जरिए कुल 17.61 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। निवेशक इस आईपीओ में 29 जनवरी तक बोली लगा सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़े जानकारों के मुताबिक, इस इश्यू का अलॉटमेंट 30 जनवरी को तय किया जाएगा, जबकि 2 फरवरी को शेयर निवेशकों के डीमैट खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो कस्तूरी मेटल कंपोजिट के शेयर 3 फरवरी को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 61 से 64 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इश्यू में एक लॉट में 2,000 शेयर रखे गए हैं, यानी न्यूनतम निवेश के लिए निवेशकों को 1,28,000 रुपये लगाने होंगे। रिटेल निवेशकों को अधिकतम दो लॉट यानी 4,000 शेयरों के लिए आवेदन करने की अनुमति है, जिसके लिए अधिकतम 2,56,000 रुपये का निवेश करना होगा।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन भावनगर मंडल द्वारा 77वाँ गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार, 26 जनवरी 2026 को पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) द्वारा संचालित बाल मंदिर एवं किड्स हट स्कूलों में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी वर्मा तथा मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा तिरंगा ध्वज फहराया गया।

कार्यक्रम के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की पदाधिकारी सदस्याएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति के गीतों, गतिविधियों एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रप्रेम की भावना का सुंदर प्रदर्शन किया।

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सेवा एवं संवेदना के भाव को आगे बढ़ाते हुए मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर परा में भर्ती 18 मरीजों एवं 10 सफाई

कर्मचारियों को WRWWO की अध्यक्ष महोदया एवं संगठन की अन्य सदस्याओं के कर-कमलों से उपहार एवं फल वितरित किए गए। यह आयोजन संगठन की सामाजिक प्रतिबद्धता एवं मानवीय मूल्यों को दर्शाने वाला रहा।

इस अवसर पर WRWWO भावनगर की अध्यक्ष महोदया ने सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ाव, सहयोग और सेवा भावना को सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में महिला कल्याण संगठन की सभी सदस्याओं का योगदान सराहनीय रहा।

भावनगर रेलवे मंडल पर पूरे उत्साह के साथ मनाया गया 77वाँ गणतंत्र दिवस

भावनगर रेलवे मंडल पर 26 जनवरी, 2026 (सोमवार) को 77वाँ गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री वर्मा ने रेलवे स्टेडियम भावनगर परा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा झंडे को सलामी दी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार मंडल सुरक्षा आयुक्त (रेलवे सुरक्षा बल) श्री प्रेमनाथ राय की आगवानी में भारत स्काउट एण्ड गाइड, सेंट जॉन एम्ब्युलेंस, नर्सिंग युनिटों व रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने इस अवसर पर परेड की मनोहर झांकी प्रस्तुत की, जिसका निरीक्षण मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा किया गया। उसके पश्चात मंडल रेल प्रबंधक ने इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता के संदेश का वाचन किया तथा उन्होंने

समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारजनों एवं नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित बाल मंदिर और कीड्स हट तथा पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय भावनगर परा के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर सुख, शांति एवं समृद्धि के प्रतीक तिरंगे रंगों के गुब्बारों को गगन में मुक्त कर एकता, आशा और उज्जवल भविष्य का सशक्त संदेश दिया गया।

इस अवसर पर मंडल कार्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवारजन एवं नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अन्त में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कार्यक्रम को सफल बानाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 कर्मचारियों को भी मंडल रेल प्रबंधक द्वारा नकद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण समिति-भावनगर मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने वाले नन्हें मुन्हें बच्चों की काफी प्रशंसा की। भावनगर रेलवे मंडल के सभी स्टेशनों, हेल्थयूनिटों और कोचिंग डिपो में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

भारत- ईयू एफटीए, माननीय प्रधानमंत्री की दूर की सोच वाली लीडरशिप में एक बड़ी कामयाबी; निर्यात प्रतिस्पर्धा को बदलने और वैश्विक वैल्यू चेन के साथ भारत के एकीकरण को गहरा करने के लिए तैयार: फियो अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन

नई दिल्ली; 27 जनवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (फियो) ने भारत-यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता (भारत- ईयू एफटीए) के ऐतिहासिक ऐलान के बाद, भारत के माननीय प्रधानमंत्री की दूर की सोच वाली लीडरशिप, दूर की स्ट्रेटेजिक सोच और फैसले लेने वाली डिप्लोमेसी की दिल से तारीफ़ की है। इस ऐतिहासिक समझौते का ऐलान आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट महामहिम सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने नई दिल्ली में हुए 16वें भारत-ईयू समिट में मिलकर किया। भारत - ईयू एफटीए का पूरा होना भारत की वैश्विक इकोनॉमिक यात्रा में एक अहम पड़ाव है और यह व्यापार से होने वाली ग्रोथ, इकोनॉमिक सुधारों और वैश्विक एकीकरण के लिए भारत सरकार के पक्के प्रतिबद्धता का सबूत है। यह समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन को भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर मज़बूत करता है, जो खुले बाज़ार, पहले से तय और सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध हैं। फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि यह 2022 में बातचीत फिर से शुरू होने के बाद से सरकार के मज़बूत राजनीतिक इरादे के साथ लगातार, नतीजे पर आधारित बातचीत का नतीजा है, जो एक संतुलित, मॉडर्न और नियमों पर आधारित इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाने के साझा नज़रिए को दिखाता है।

यूरोपियन यूनियन भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। वित्त वर्ष 2024–25 में, भारत - ईयू का वस्तु का आपसी व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपये (136.54 बिलियन डॉलर) था, जिसमें 6.4 लाख करोड़ रुपये (75.85 बिलियन डॉलर) का निर्यात और 5.1 लाख करोड़ रुपये (60.68 बिलियन डॉलर) का इंपोर्ट शामिल था। सेवा क्षेत्र में व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपये (83.10 बिलियन डॉलर) तक पहुँच गया। भारत और ईयू मिलकर दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हैं, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा हैं—यह एक ऐसा अवसर है जिसे भारत सरकार ने इस बदलाव लाने वाले एग्रीमेंट के ज़रिए स्ट्रेटेजिक तरीके से खोला है।

श्री रल्हन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के डायनैमिक और रिफॉर्म-ओरिएंटेड लीडरशिप में भारत- ईयू एफटीए का सफल होना एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है, जो भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ाएगा और वैश्विक वैल्यू चेन के साथ भारत के सहयोग को बढ़ावा देगा। यह एग्रीमेंट भारतीय निर्यातकों के लिए वस्तु और सेवा क्षेत्र में, खासकर लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स, एमएसएमई, महिला एंटरप्रेन्योर्स, कारीगरों और युवाओं को मज़बूत बनाने के लिए पहले कभी नहीं देखा गया मार्केट एक्सेस खोलता है—जो सरकार के इनक्लूसिव ग्रोथ एजेंडा के मुख्य फोकस एरिया हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 33 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात पर 10 प्रतिशत तक टैरिफ खत्म होने से, एफटीए टेक्सटाइल, कपड़े, लेदर, फुटवियर, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, मरीन प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल जैसे खास सेक्टर को तुरंत और ठोस फायदा देगा। इन फायदों से ज़्यादा निर्यात, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा और वैश्विक व्यापार में जमीनी स्तर पर मजबूत भागीदारी होगी, जिससे निर्यात से होने वाली खुशहाली के सरकार के विजन को मजबूती मिलेगी।

इस समझौते में वस्तु और सेवा क्षेत्र का व्यापार, ओरिजिन के नियम, कस्टम में आसानी, व्यापार उपचारों और डिजिटल व्यापार और एमएसएमई जैसे उभरते हुए सेक्टर पूरी तरह से शामिल हैं। इसमें नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने के लिए मजबूत सिस्टम शामिल हैं – जो बेहतर रेगुलेटरी सहयोग, ट्रांसपेरेंट एसपीएस उपायों और आसान कस्टम प्रोसेस के ज़रिए ईयू रेगुलेटर्स के साथ सरकार के प्रोएक्टिव जुड़ाव का नतीजा है । ऑटोमोबाइल सेक्टर में सोच-समझकर और कोटा- आधारित लिबरलाइजेशन से ईयू मैन्युफैक्चरर्स को भारत में एडवांस्ड मॉडल पेश करने की इजाज़त मिलेगी, साथ ही सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के साथ जुड़े भविष्य के मौके भी बनेंगे। भारतीय उपभोक्ताओं को हाई-टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स तक बेहतर एक्सेस और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से फायदा होने की उम्मीद है। चाय, कॉफी, मसाले, फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड्स के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस के साथ एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा, जबकि सरकार ने डेयरी और अनाज जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को समझदारी से सुरक्षित रखा है, जिससे किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।

एफटीए आईटी/आईटीईएस, प्रोफेशनल सर्विसेज़, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज़, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और दूसरी बिजनेस सर्विसेज़ सहित सर्विसेज़ में कमर्शियली सार्थक प्रतिबद्धता देता है। 144 ईयू सब-सेक्टर्स में अनुमानित मार्केट एक्सेस भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अवसरों को काफी बढ़ाएगा, जबकि रेसिप्रोकल एक्सेस भारत में हाई-टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा। प्रोग्रेसिव मोबिलिटी प्रोविजन्स भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वैश्विक अवसरों को प्राप्त करने के लिए सरकार की लगातार कोशिशों को दिखाते हैं, जिसमें शॉर्ट-टर्म बिजनेस ट्रैवल, इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट पर सर्विस सप्लायर्स, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स और डिपेंडेंट्स के लिए काम के अधिकार शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के प्रैक्टिशनर्स को ईयू सदस्य देशों में अपने टाइटल के तहत काम करने की मान्यता दिलाई है, जहाँ ऐसे तरीकों को रेगुलेट नहीं किया जाता है - यह एक महत्वपूर्ण राजनयिक और सांस्कृतिक उपलब्धि है जो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह समझौता टीआरआईपीएस के तहत बौद्धिक संपदा सुरक्षा को मजबूत करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को मान्यता देता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें सीबीएएम कंप्लायंस से संबंधित सहायता भी शामिल है।

श्री रल्हन ने दोहराया कि भारत- ईयू एफटीए, सरकार के हाल ही में ब्रिटेन और ईएफटीए के साथ हुए एफटीए के साथ मिलकर, भारतीय निर्यातकों के लिए पूरे यूरोपीय बाजार को प्रभावी ढंग से खोलता है, जो भारत की व्यापार कूटनीति में एक रणनीतिक सफलता है। यह ऐतिहासिक समझौता 'विकसित भारत 2047' के विजन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, और भारत को एक लचीले, प्रतिस्पर्धी और दूरदर्शी वैश्विक व्यापार नेता के रूप में स्थापित करता है।

भारत-ईयू एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव में एक नए युग की शुरुआत करता है, जो भारत सरकार की रणनीतिक स्पष्टता, बातचीत की ताकत और दीर्घकालिक विजन को दर्शाता है - 27-सदस्यीय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है, साथ ही भविष्य की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत नींव रखता है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया

महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने इस पावन अवसर पर सभी रेलकर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई दीं

पहली तस्वीर में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। दूसरी तस्वीर में श्री गुप्ता उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए तथा अंतिम तस्वीर में महाप्रबंधक मुंबई के महालक्ष्मी स्पोर्ट्स ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सामारोहिक परेड का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पश्चिम रेलवे पर 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मुंबई के महालक्ष्मी स्पोर्ट्स ग्राउंड में भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। महाप्रबंधक ने औपचारिक परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च-पास्ट की सलामी भी ली।श्री गुप्ता ने इस गरिमामय अवसर पर उपस्थित रेलकर्मियों एवं उनके परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए सभा को संबोधित किया। समारोह के आरंभ में महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता का स्वागत पश्चिम रेलवे के आईजी सह प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अजय सदानी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती नीता गुप्ता, पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार, प्रमुख विभागाध्यक्षों सहित अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने अपने गणतंत्र दिवस संदेश में पश्चिम रेलवे द्वारा हाल ही में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया। महाप्रबंधक ने वर्ष 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित दक्षता शील्ड की सर्वाधिक संख्या प्राप्त करने पर सम्पूर्ण पश्चिम रेलवे टीम की प्रशंसा की। अपने संबोधन के समापन पर श्री गुप्ता ने सभी कर्मचारियों से विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नवोन्मेष, नई ऊर्जा और समर्पण के साथ और अधिक परिश्रम करने का आह्वान किया।

फोटो कैप्शनःपश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती नीता गुप्ता को जगजीवन राम अस्पताल को उपयोगी वस्तुएँ दान करते हुए दिखाई दे रही हैं।

श्री विनीत ने बताया कि इस शुभ अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती नीता गुप्ता द्वारा पश्चिम रेलवे के जगजीवन राम अस्पताल (JRH) में मरीजों के उपयोग हेतु स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन केतली दान की गईं, जिन्हें पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. अतुल शर्मा को सौंपा गया।

इस कार्यक्रम के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा डॉग स्क्वाड शो का आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर देशभक्ति गीतों एवं नृत्य प्रस्तुतियों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

सोना वायदा में 2763 रुपये और चांदी वायदा में 27827 रुपये का अधिक ऊछालः क्रूड ऑयल वायदा 44 रुपये फिसला

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 431942.41 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 91733.66 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 340187.74 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 45400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4547.63 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 80393.72 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 158674 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159820 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 157500 रुपये पर पहुंचकर, 156037 रुपये के पिछले बंद के सामने 2763 रुपये या 1.77 फीसदी बढ़कर 158800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 741 रुपये या 0.55 फीसदी की तेजी के संग 135935 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 90 रुपये या 0.53 फीसदी की तेजी के संग 16996 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी फरवरी वायदा 157478 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159899 रुपये और नीचे में 157478 रुपये पर पहुंचकर, 2481 रुपये या 1.58 फीसदी की तेजी के संग 159153 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 164499 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 167499 रुपये और नीचे में 164453 रुपये पर पहुंचकर, 163137 रुपये के पिछले बंद के सामने 3334 रुपये या 2.04 फीसदी की तेजी के संग 166471 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 339824 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 364821 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 339824 रुपये पर पहुंचकर, 334699 रुपये के पिछले बंद के सामने 27827 रुपये या 8.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 362526 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 27261 रुपये या 8.03 फीसदी की बढ़त के साथ 366550 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 27305 रुपये या 8.05 फीसदी की तेजी के संग 366624 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। मेटल वर्ग में 5578.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 3.45 रुपये या 0.26 फीसदी की मजबूती के साथ 1319.95 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 6.5 रुपये या 2.06 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 322.75 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 1.75 रुपये या 0.55 फीसदी की मजबूती के साथ 319.8 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 25 पैसे या 0.13 फीसदी टूटकर 191.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5266.44 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5570 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5623 रुपये और नीचे में 5475 रुपये पर पहुंचकर, 44 रुपये या 0.78 फीसदी औंधकर 5586 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 37 रुपये या 0.66 फीसदी की गिरावट के साथ 5591 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 332 रुपये के भाव पर खूलकर, 348.5 रुपये के दिन के उच्च और 332 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 328.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 18.6 रुपये या 5.66 फीसदी की तेजी के संग 347.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 18.2 रुपये या 5.53 फीसदी की तेजी के संग 347.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 1029.8 रुपये पर खूलकर, 1.2 रुपये या 0.12 फीसदी की तेजी के संग 1026.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 38491.19 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 41902.53 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4502.73 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 339.54 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 38.69 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 679.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 879.90 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 4371.41 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 12.07 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20338 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 101976 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 40486 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 588427 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 66014 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14212 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 39403 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 99532 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 19552 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 21873 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 44500 पॉइंट पर खूलकर, 45407 के उच्च और 44500 के नीचले स्तर को छूकर, 1599 पॉइंट बढ़कर 45400 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 42.3 रुपये की गिरावट के साथ 234.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 13.55 रुपये की बढ़त के साथ 40.25 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 161000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 600 रुपये की गिरावट के साथ 113 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 332000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 22549.5 रुपये की बढ़त के साथ 30859.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.53 रुपये की बढ़त के साथ 35.96 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.4 रुपये की बढ़त के साथ 10.82 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 11.3 रुपये की बढ़त के साथ 205 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.1 रुपये की गिरावट के साथ 13.7 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1195 रुपये की गिरावट के साथ 116.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 257000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 19.5 रुपये की बढ़त के साथ 20 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.55 रुपये की गिरावट के साथ 7.75 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.83 रुपये की बढ़त के साथ 5.8 रुपये हुआ।